राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ के 81 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी

रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिली है। रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'पैमाना' रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की कुल 81 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे राजस्थान की विकास यात्रा को नई दिशा मिल रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राजस्थान निवेश, उद्योग, पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल प्रदेश की आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी, बल्कि रोजगार, व्यापार, परिवहन और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जल्द शुरू होने की तैयारी में है। बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही इस परियोजना की लागत करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए है।

इस रिफाइनरी के शुरू होने से राजस्थान सहित पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत होगी। साथ ही हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

इसके अलावा एचपीसीएल की ओर से बाड़मेर में 461 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल परियोजना पर भी काम चल रहा है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 19 ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें 25 हजार करोड़ रुपए की राजस्थान पार्ट-1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तक फैली हुई है। इससे ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और राजस्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। उत्तर-पश्चिम रेलवे की 23 परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत करीब 1 लाख 64 हजार 998 करोड़ रुपए है। इनमें गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से गुजरने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रमुख परियोजना है, जिसकी लागत करीब 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए है और इसका कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवगढ़ मदारिया-नाथद्वारा रेललाइन, नाथद्वारा टाउन परियोजना, पुष्कर-मेड़ता सिटी रेललाइन और पोकरण-रामदेवरा नई रेललाइन जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा अजमेर-चंदेरिया दोहरीकरण, सादुलपुर-चूरू दोहरीकरण, धौलपुर-सरमथुरा गेज परिवर्तन, सवाईमाधोपुर-जयपुर रेलवे लाइन और आगरा फोर्ट-बांदीकुई दोहरीकरण जैसी कई बड़ी परियोजनाएं भी प्रदेश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत कर रही हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क नेटवर्क के विस्तार का काम भी तेज गति से जारी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचएआई की ओर से करीब 18 हजार करोड़ रुपए की 28 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसकी लागत 6 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक है।

इसके अलावा एनएच-25 पर पचपदरा-बागुंडी फोरलेन, ब्यावर-गोमती फोरलेन, फतेहपुर-मंडावा-झुंझुनूं बाईपास और नाथद्वारा से भटेवर तक सड़क उन्नयन जैसे कई कार्य लगभग पूर्णता की ओर हैं।

राजस्थान में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से करीब 2 हजार 874 करोड़ रुपए की तीन बड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। बूंदी-कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को हाड़ौती क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस परियोजना की लागत करीब 1 हजार 507 करोड़ रुपए है और इसे नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उदयपुर एयरपोर्ट पर नया एकीकृत टर्मिनल और जोधपुर एयरपोर्ट पर घरेलू यात्री टर्मिनल परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।'पैमाना' रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान अब आधुनिक और मजबूत आधारभूत संरचना वाले राज्यों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे, सड़क, ऊर्जा, रिफाइनरी और एयरपोर्ट परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में विकास का नया ढांचा तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राजस्थान निवेश, उद्योग, पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

श्रीलंका की राजधानी में जयपुर फुट निर्माण का स्थायी केन्द्र स्थापित हुआ

श्रीलंका का दूसरा केन्द्र जाफना में 26 जून से सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा

जयपुर। विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के तकनीकी सहयोग से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जयपुर फुट निर्माण का एक स्थायी केन्द्र स्थापित हो गया है और कार्य करने लगा है । इसी प्रकार का एक और केन्द्र श्रीलंका के बड़े शहर जाफना में इस माह स्थापित हो जाएगा।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने बताया कि उक्त दो केन्द्रों की स्थापना में बी.एम.वी.एस.एस. के चेन्नई केन्द्र के अध्यक्ष डॉ. विनोद सुराणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉ. सुराणा जिनके स्वयं के पैतृक निवास में चेन्नई केन्द्र कार्यरत है ने श्रीलंका की संस्था ऑल सिलोन बुद्धिस्ट कांग्रेस (ए.सी.बी.सी.) से आपसी सहयोग के प्रयास किए जो सफल रहे । ऑल सिलोन बुद्धिस्ट कांग्रेस ने कोलंबो केन्द्र के लिए मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया था जिसे बी.एम.वी.एस.एस. ने भिजवा दिया। इस केन्द्र का नाम साधी सुया रखा गया है, जहाँ विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर दिए जाएंगे, उद्घाटन समारोह में डॉ. सुराणा उपस्थित थे।

डी.आर. मेहता ने बताया कि श्रीलंका का दूसरा केन्द्र जाफना में 26 जून से सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। कोलंबो केन्द्र बी.एम.वी.एस.एस. के जयपुर में प्रशिक्षित श्रीलंका की सेना के तकनीशियन संचालित करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से श्रीलंका के तकनीशियनों को जयपुर के बी.एम.वी.एस.एस. के केन्द्र में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। डी.आर. मेहता ने बताया कि जाफना के केन्द्र को संचालित करने के लिए जयपुर बी.एम.वी.एस.एस. के दो तकनीशियन जाएंगे, जहाँ स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डी.आर. मेहता ने बताया कि वेस्ट इण्डीज के त्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी पोर्ट-ऑफ-स्पेन में हाल ही में एक स्थायी केन्द्र जयपुर फुट यू.एस.ए. के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन त्रिनिडाड-टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिस्सेसर प्रसाद ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उपस्थिति में किया था। इस केन्द्र में बी.एम.वी.एस.एस. के तकनीशियन गजानन्द लाम्बा वहाँ तीन माह रहकर प्रशिक्षण देंगे। उल्लेखनीय है कि त्रिनिडाड और टोबैगो में सितम्बर 2025 में एक विशेष शिविर लगाकर 803 विकलांगों का पुर्नवास किया गया था। इसी प्रकार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2011, वर्ष 2012 और वर्ष 2024 में विशेष शिविरों में कुल 2759 विकलांगों को पुर्नवास किया गया । इसी तरह कोलंबों में 2011, 2022 और 2024 में तीन अलग-अलग शिविरों में 1408 विकलांगों का पुर्नवास किया गया ।

रूफ टॉप सौर ऊर्जा में बढ़ रही प्रदेश की भागीदारी

मई माह में अब तक का सर्वाधिक 26632 प्लांट इंस्टॉलेशन हुआ

जयपुर । प्रदूषणरहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी पहल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान की भागीदारी बढ़ रही है। बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति पाने के लिए विद्युत उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं।

योजना के अन्तर्गत हाल के मई माह में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद यह प्रदेश में किसी भी एक माह का अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है।

इसके अन्तर्गत जोधपुर डिस्कॉम में 9316, जयपुर डिस्कॉम में 9204 तथा अजमेर डिस्कॉम में 8,112 उपभोक्ताओं ने अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाएं हैं।

इस दौरान सर्वाधिक 5484 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले में इंस्टॉल हुए हैं। इसके पश्चात् श्रीगंगानगर में 3264, हनुमानगढ़ में 2084, सीकर में 1606 तथा झुंझुनूं में 1534 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए।

ज्ञात रहे कि राजस्थान डिस्कॉम्स इस योजना को गति दे रहे हैं। इसके अन्तर्गत मई माह में डिस्कॉम के कार्मिकों ने 27 हजार 700 से अधिक उपभोक्ताओं के रूफ टॉप सोलर आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया। यह किसी भी माह में सर्वाधिक आवेदनों का निरीक्षण है।

डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बीते दिनों तीनों वितरण निगमों के सभी सर्किलों में निरीक्षण के प्रकरणों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी से लाने के निर्देश दिए थे। इसी का नतीजा रहा कि अभियंताओं ने सर्वाधिक निरीक्षण प्रक्रियाओं को सम्पन्न किया जिससे माह सर्वाधिक 31 हजार 437 उपभोक्ताओं को सबसिडी भी प्राप्त हुई। साथ ही, 177 नए वेंडरों को भी योजना से जोड़ा गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2.17 लाख रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। भारत सरकार से इसके लिए लगभग 1460 करोड़ रूपए की सब्सिडी भी लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

विधानसभाध्यक्ष देवनानी करेंगे चारधाम के दर्शन

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उत्तराखंड की पांच दिवसीय यात्रा में चार धाम के दर्शन करेंगे। देवनानी जयपुर से मंगलवार को प्रातः 10 बजे वायुयान से देहरादून जाएंगे। देवनानी ने कहा कि चार धाम की यात्रा पवित्र और आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। देवनानी इस यात्रा को पारंपरिक क्रम में ही पूरा करेंगे। पारंपरिक क्रम के अनुसार यह यात्रा यमुनोत्री से आरंभ होकर गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पर पूरी होती है। देवनानी ने बताया कि यमुनोत्री धाम देवी यमुना, गंगोत्री धाम देवी गंगा, केदारनाथ धाम भगवान शिव और बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है।

बर्फ फैक्ट्री, बीएमसी व घरों में बिजली चोरी पकड़ी

■ 12 मामलों में 20 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना

जयपुर । जयपुर विद्युत वितरण निगम की सतर्कता शाखा ने सोमवार को कालवाड़ विद्युत सब-डिवीजन क्षेत्र में गहन सतर्कता जांच के दौरान बर्फ की एक फैक्ट्री, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (बीएमसी) व 10 आवासीय परिसरों में विद्युत चोरी पकडी। इन सभी मामलों में वीसीआर भरकर करीब 20 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) चेतन स्वरूप भंसाली के नेतृत्व में सतर्कता दल ने ग्राम पचार में एक घरेलू कनेक्शन की जांच की, जिसमें पाया गया कि विद्युत का उपभोग दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (बीएमसी) के संचालन में किया जा रहा था। इस पर करीब 2 लाख 43 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। सर्वेश्वर विहार स्थित एक बर्फ फैक्ट्री में मीटर से छेडछाड कर विद्युत चोरी की जा रही थी, जिस पर 4 लाख 37 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार मांगू बाबा की ढाणी, पचार, गुजारिया वाली ढाणी, लालरपुरा के 4 आवासीय परिसरों में एलटी पोल से सीधे तार जोडकर विद्युत चोरी की जा रही थी। इन पर करीब 5 लाख 84 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी 6 परिसरों में संयुक्त रूप से 49.83 कि.वॉट का विद्युत लोड पाया गया।

अधिशाषी अभियंता के.सी.गुप्ता के निर्देशन में ग्राम रामकुंई, पचार, शबरामपुरा, पुनियां की ढाणी में एलटी पोल से सीधे अवैध तार जोडकर 6 आवासीय परिसरों में विद्युत चोरी के मामले पकडे गये। जिनमें करीब 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

अजेय कुमार के नेतृत्व में राजस्थान में संगठन को मिलेगी नई गति : मदन राठौड़

■ भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन की नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर्ष जताया

जयपुर (कासं)। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ संगठनकर्ता एवं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार को राजस्थान भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

मदन राठौड़ ने कहा कि अजेय कुमार का संगठनात्मक अनुभव, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण तथा कुशल नेतृत्व राजस्थान भाजपा संगठन को नई ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में भाजपा राजस्थान संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा तथा संगठन विस्तार और जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार के संगठनात्मक अनुभव और कुशल नेतृत्व में प्रदेश संगठन और अधिक सशक्त होगा। राजनीतिक एवं संगठनात्मक क्षेत्रों में अजेय कुमार को एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में वर्ष 1997 में श्रीनगर गढ़वाल से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले अजेय कुमार ने संघ और भाजपा संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है।

श्रीनगर, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में नगर प्रचारक, ऊधमसिंह नगर में जिला प्रचारक तथा अल्मोड़ा विभाग के विभाग प्रचारक के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं बिजनौर विभाग के विभाग प्रचारक के रूप में भी संगठन को मजबूत किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश महामंत्री संगठन की नियुक्ति पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान जैसे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश में प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार की नियुक्ति उनके संगठनात्मक कौशल, प्रभावी नेतृत्व क्षमता और परिणाम देने वाली कार्यशैली की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। यह निर्णय भाजपा नेतृत्व के उस विश्वास को भी दर्शाता है कि अनुभवी एवं सक्षम संगठनकर्ता ही संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, ज्योति मिर्धा, अल्का मूंदडा, सरिता गेना, बिहारी लाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू भाई मईडा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भूपेंद्र सैनी, कैलाश मेघवाल, मिथिलेश गौतम ने भी संगठन महामंत्री की नियुक्त पर हर्ष व्यक्त किया।

जर्मन शेफर्ड के हमले में 4 वर्षीय मासूम गंभीर घायल

जयपुर। पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग द्वारा 4 वर्षीय मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। डॉग ने बच्ची के सिर और आंख के पास हमला कर उसे बुरी तरह नोंच डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

हैड कांस्टेबल रामनिवास ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी स्थित राधाकुंज धोलाई की एक रेजीडेंसी में संतोष कुमार माथा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी 4 वर्षीय पुत्री आद्रिका खंडेलवाल 24 मई की रात करीब 8:30 बजे अपने फ्लैट से दो घर छोड़कर रहने वाले बच्चों को बुलाने गई थी।

परिजनों के अनुसार जैसे ही बच्ची ने पडौसी फ्लैट का डोरबेल बजाया और गेट खुला, तभी अंदर से तेजी से दौड़कर आए पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग ने उस पर अचानक हमला कर दिया। डॉग ने बच्ची के सिर और आंख के ऊपरी हिस्से को बुरी तरह नोंच लिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी।

आरोप है कि घटना के बाद बच्ची की मदद करने के बजाय पडौसी ने पहले डॉग को अंदर खींच लिया और इसके बाद अपने फ्लैट का गेट बंद कर लिया। इस दौरान बच्ची दर्द से तड़पती रही। शोर सुनकर पहुंचे अन्य पडौसियों ने उसे संभाला और सोसायटी कॉरिडोर में लाकर प्राथमिक सहायता दी।

परिजन उसे तत्काल एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के सिर और आंख के पास गहरे घाव हैं और उसकी प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए मंगलवार को सर्जनों द्वारा जांच की जाएगी।

पीएम पोषण योजना में केन्द्र सरकार ने 954 करोड़ रुपए मंजूर किए

भोजन की पौष्टिकता और गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश की स्कूलों का औचक निरीक्षण करें अधिकारी : मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की "पी.एम. पोषण योजना" की वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने इस योजना में राज्य के लिए 953.97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई।

■ बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने भी श्रीकृष्ण भोग योजना संचालित कर वर्ष 2025-26 में 60.54 लाख भोजन थाली परोसी है। भोजन की गुणवत्ता विद्यार्थियों की माताएं और महिला अभिभावक जांचती है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा राजेश यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यूडीएच आलोक गुप्ता, सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अम्ब्रीश कुमार संयुक्त सचिव वित्त (व्यय) डॉ. भारती दीक्षित, आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मलावत, मिड-डे-मिल आयुक्त विश्व मोहन शर्मा तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा पी.एम.पोषण योजना से जुड़े अफसर मौजूद थे।

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न विद्यालयों में निरंतर भ्रमण एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव को श्री कृष्ण भोग योजना से भी अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि यह योजना राज्य सरकार का नवाचार है, जिसका बेहतरीन प्रभाव देखा गया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इस नवाचार की प्रशंसा की है।

श्रीकृष्ण भोग योजना ना केवल बच्चों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, बल्कि कुपोषण एवं एनिमिया जैसी समस्याओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना में वर्ष 2025-26 में 60.54 लाख भोजन थाली परोसी गई।

मुख्य सचिव को अतिथि माता कॉन्सेप्ट से भी अवगत कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों की माताओं एवं महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता और पोषण मानकों एवं वितरण व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण करवाया जाता है। साथ ही बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन के स्वाद और गुणवत्ता परीक्षण के लिए भोजन भी करवाया जाता है।

जिस पर माताएं एवं महिला अभिभावक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाती हैं। अभी तक 55 लाख 19 हजार 810 अतिथि माताओं द्वारा विद्यालयों का भ्रमण कर मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का अवलोकन किया है।

ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उडाने वालों पर पुलिस का शिकंजा

3 बड़े वाहन सीज, अब तक 86 हजार से अधिक पर कार्रवाई

जयपुर। राजधानी में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उडाने वाले आदतन और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त अभियान शुरू किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम (संशोधित 2019) के तहत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी है।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) योगेश गोयल ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से ड्राइविंग, ब्लैक फिल्म का उपयोग, अनाधिकृत मॉडिफिकेशन तथा बार-बार नियम तोड़ने वाले आदतन वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दौरान तीन बड़े मामलों में वाहनों को सीज किया गया है। इनमें शामिल हैं बस नंबर 071319, जिसके चालक ने 67 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया । बस नंबर 054377, जिस पर 63 बार नियम उल्लंघन दर्ज है । थार नंबर 607445, जिसे 6 बार नियम तोड़ने के बाद दोबारा उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त अब तक 37 अन्य आदतन वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।

30-31 मई को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शहरभर में व्यापक कार्रवाई की। इस दौरान ब्लैक फिल्म के 451 मामले, ओवरस्पीडिंग के 3108 मामले,अनाधिकृत मॉडिफिकेशन के 119 मामले,शराब पीकर वाहन चलाने के 36 मामले और मॉडिफाइड साइलेंसर के 31 मामले दर्ज किए गए इस अभियान के दौरान 25 से अधिक दोपहिया वाहनों के अवैध साइलेंसर हटवाए गए तथा 100 से अधिक चौपहिया वाहनों से अनाधिकृत बंपर एवं बुलगार्ड हटवाए गए। पुलिस के अनुसार अब तक कुल 86,157 वाहनों के खिलाफ चालान एवं शमन की कार्रवाई की जा चुकी है, जो इस अभियान की व्यापकता को दर्शाता है।

15697 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से अब तक 42,358 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने तथा 558 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेजी गई है। इनमें से अब तक 15,697 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहन के पेंडिंग चालानों की स्थिति की जांच आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करें और समय पर उनका भुगतान सुनिश्चित करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों को वर्चुअल कोर्ट में भेजा जा चुका है, उनका निस्तारण अब ट्रैफिक पुलिस स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मामलों की स्थिति जानने के लिए संबंधित वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।